IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"मधेसी क्षेत्र का भू– राजनीतिक महत्वः भारत–नेपाल संबंधों के लिए रणनीतिक निहितार्थ"

[1]डॉ. शक्ति जायसवाल
असिस्टेंट प्रोफेसर
बुद्ध विद्यापीठ पीजी कॉलेज
राजनीति विज्ञान विभाग
(सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु)
सिद्धार्थनगर

[2]भव्या राय
शोधार्थी
बुद्ध विद्यापीठ पीजी कॉलेज
राजनीति विज्ञान विभाग
(सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु)
सिद्धार्थनगर

सारः यह शोधपत्र मधेसी तराई को भारत–नेपाल संबंधों की धुरी के रूप में देखता है। सीमा–भूमि भू–राजनीति को छोटे राज्यों की सुरक्षा दुविधा के साथ जोड़ते हुए, यह सुगौली संधि से लेकर 2015 की नाकाबंदी तक, दो शताब्दियों के संघर्ष का पुनर्निर्माण करता है, और इस क्षेत्र के समकालीन भार, नेपाल की जनसंख्या का 21 प्रतिशत, सीमा शुल्क राजस्व का 4/5 भाग, और पाइपलाइनों और 400 केवी ग्रिडों का एकमात्र संरेखण, जो भारत के ऊर्जा गणित का आधार हैं, का परिमाणन करता है। मूल क्षेत्रीय साक्षात्कार और जनगणना–व्यापार के अलग–अलग आँकड़े बताते हैं कि कैसे मधेसियों का कम प्रतिनिधित्व बार–बार घरेलू अशांति को जन्म देता है जो 1,751 किलोमीटर की खुली सीमा तक फैल जाती है, और बाहरी शक्तियों मुख्यतः चीन के बीआरआई—को काठमांडू के हेजिंग विकल्पों को नया रूप देने के लिए आमंत्रित करती है। यह अध्ययन इन परस्पर विरोधी दबावों को एक "सीमा सुरक्षा परिसर" में चित्रित करता है और तराई आर्थिक गलियारे, सममित संघीय वित्तपोषण, और त्रि–राष्ट्रीय आपदा प्रोटोकॉल को बलपूर्वक अस्थिरता से सहकारी परस्पर निर्भरता की ओर बढ़ने वाले क्रमिक मार्गों के रूप में प्रस्तावित करता है। निष्कर्ष तुलनात्मक सीमा अध्ययनों को और गहन बनाते हैं और दक्षिण एशियाई क्षेत्रवाद के हिमालयी संदर्भ में उप–क्षेत्रीय संपर्क नीति के लिए कार्यान्वयन योग्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

मुख्य शब्दः मधेस, तराई, सीमावर्ती भू–राजनीति, बेल्ट एंड रोड पहल, आर्थिक गलियारा आदि।

परिचय

सीमावर्ती क्षेत्र अक्सर भू–राजनीतिक "अग्रदूतों" के रूप में कार्य करते हैं जहाँ घरेलू राजनीति, सुरक्षा तर्क और अंतरराष्ट्रीय पहचान एक–दूसरे से मिलती हैं। नेपाल का दक्षिणी तराई क्षेत्र जिसे मधेश कहा जाता है इस गतिशीलता का उदाहरण है। भारत के साथ लगभग पूरी 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा तक फैला मधेशी क्षेत्र 61 लाख लोगों (नेपाल की जनसंख्या का लगभग 21%) का घर है और यह देश का सबसे घनी आबादी वाला प्रांत है, फिर भी यह राष्ट्रीय भूभाग का मुश्किल से 6. 5% ही घेरता है[1]।

इस क्षेत्र के समतल गंगा के मैदान में चार प्रमुख सीमा शुल्क गलियारे (बीरगंज–रक्सौल, विराटनगर–जोगबनी, भैरहवा–सुनौली, नेपालगंज–रुपैदिहा) हैं, जो नेपाल के दो–तिहाई से अधिक व्यापारिक व्यापार और उसके पेट्रोलियम आयात का बड़ा हिस्सा ढोते हैं।ऐतिहासिक रूप से, तराई के संबंध 1950 की शांति और मैत्री संधि का आधार रहे हैं, जिसने दोनों राज्यों के बीच वीजा–मुक्त आवागमन और श्रम संचलन को संस्थागत रूप दिया। फिर भी, यही खुला ढाँचा तब विवाद का विषय बन गया जब मधेसी समूहों ने नेपाल के 2015 के संविधान में कथित कम प्रतिनिधित्व का विरोध किया, जिसके कारण 135 दिनों की नाकेबंदी हुई जिससे ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति बाधित हुई और द्विपक्षीय संबंध 1990 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए [2]। इस संकट ने काठमांडू में वैकल्पिक पारगमन मार्गों की खोज को भी गति दी। सबसे स्पष्ट रूप से 2016 नेपाल–चीन पारगमन परिवहन समझौता और उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाएँ—जिससे उस सीमावर्ती क्षेत्र में महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई जिसे कभी भारत का अनन्य प्रभाव क्षेत्र माना जाता था[3]।

इस पृष्ठभूमि में, मधेसी क्षेत्र की भू–राजनीतिक प्रमुखता इक्कीसवीं सदी में भारत–नेपाल रणनीतिक संपर्क को कैसे आकार देती है? सीमावर्ती भू–राजनीति के दृष्टिकोण से अभिलेखीय सामग्री, जनगणना के आंकड़ों और हालिया नीतिगत दस्तावेजों का त्रिकोणीकरण करते हुए, यह शोधपत्र (i) द्विपक्षीय संबंधों में मधेश के ऐतिहासिक विकास का पता लगाता है, (ii) इसके समकालीन जनसांख्यिकीय–आर्थिक स्वरूप का मानचित्रण करता है, (iii) भारत और नेपाल के साथ–साथ बाहरी कारकों के रणनीतिक दांव का विश्लेषण करता है, और (iv) उप–क्षेत्रीय संपर्क का लाभ उठाते हुए आवर्ती टकरावों को कम करने के लिए नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करता है।

वैचारिक और सैद्धांतिक ढाँचा

यह अध्ययन अपने विश्लेषण को दो परस्पर प्रबल साहित्यों पर आधारित करता है, सीमावर्ती भू–राजनीति और लघु–राज्य सुरक्षा दुविधा। सीमावर्ती क्षेत्रों पर शोधकार्य सीमाओं को स्थिर रेखाओं के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित स्थानों के रूप में पुनर्परिभाषित करता है जहाँ राज्य की संप्रभुता, अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाएँ और बहुस्तरीय पहचानें निरंतर एक–दूसरे के साथ संवाद करती रहती हैं[4]। एंडरसन का आधारभूत "सीमाएँ और शक्ति" मॉडल इस बात पर जोर देता है कि कैसे सीमाएँ श्रम, पूँजी और विचारों के प्रवाह को बाधित और सक्षम दोनों करती हैं, जिससे वे भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के महत्वपूर्ण स्थल बन जाते हैं।

ब्रूनेट–जैली का अंतःविषय दृष्टिकोण चार परस्पर क्रियाशील शक्तियों बाजार की नीतिगत गतिविधियाँ, राजनीतिक प्रभाव और संस्कृति को और भी उजागर करता है, जो मिलकर किसी सीमावर्ती क्षेत्र के एकीकरण या विखंडन की डिग्री को आकार देते हैं। इन अंतर्दृष्टियों को मधेश पर लागू करने से हम इसे केवल नेपाल की दक्षिणी परिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक छिद्रपूर्ण सामाजिक–स्थानिक अंतरापृष्ठ के रूप में देख सकते हैं, जिसका खुलापन सीमा पार आजीविका को बनाए रखता है और काठमांडू की राज्य–निर्माण परियोजना को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनाता है[5]।

छोटे राज्यों की सुरक्षा दुविधा भी इसी का पूरक है, जो यह मानती है कि बड़े प्रतिद्वंद्वियों के बीच स्थित भौगोलिक रूप से सीमित राज्यों को बाहरी गठबंधन और घरेलू स्वायत्तता के बीच गंभीर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कुवैत और श्रीलंका के शीत–युद्धकालीन विश्लेषणों से उत्पन्न यह अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि कैसे गठबंधन विविधीकरण या मानक अपीलों के माध्यम से भेद्यता को कम करने के प्रयास अनजाने में पड़ोसी महाशक्तियों में खतरे की धारणा को बढ़ा सकते हैं।

भारत–नेपाल संबंधों में मधेशियों का ऐतिहासिक विकास (1769 – 2015)

मधेशी क्षेत्र की भू–रणनीतिक प्रमुखता दक्षिण एशिया के आधुनिक राष्ट्र–राज्यों से बहुत पहले से है। 1769 के बाद जब गोरखा साम्राज्य ने दक्षिण की ओर विस्तार किया, तो तराई के चावल के खेतों ने न केवल उसकी हिमालयी विजयों को वित्तपोषित किया, बल्कि आंग्ल–नेपाली युद्ध (1814–1816) को भी भड़काया। इसके परिणामस्वरूप हुई सुगौली संधि ने काठमांडू के लगभग 40% निचले भूभाग को छीन लिया जिसमें आज के मधेश का अधिकांश भाग भी शामिल है—और सीमा को उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी तक धकेल दिया। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान नेपाल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करने के बाद ब्रिटेन का गणित बदल गया[6]। बदले में, लंदन ने 1860 के पूरक सीमा समझौते के तहत चार पश्चिमी तराई जिलों (बांके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर) को बहाल किया, जिसे तथाकथित नया मुलुक ("नया देश") कहा गया, जिसने नेपाल के शासन को गंगा के मैदान तक पुनः विस्तारित किया।

राणा तानाशाही (1846–1951) के दौरान खुली सीमा एक आर्थिक जीवनरेखा बन गई। मधेसी किसान ब्रिटिश भारत को चावल और लकड़ी का निर्यात करते थे, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश से मौसमी प्रवासी श्रम और प्रेषण की आपूर्ति करते थे। नेपाल की 1951 की लोकतांत्रिक क्रांति के लिए भारतीय समर्थन ने 1950 की भारत–नेपाल शांति और मैत्री संधि को मजबूत किया, जिसने वीजा–मुक्त आवागमन को संस्थागत रूप दिया और भारतीय नागरिकों को तराई में संपत्ति और व्यावसायिक अधिकार दिए जो राजनीतिक रूप से विवादास्पद बने हुए हैं[7]।

शीत युद्ध के दशकों ने इस असममित परस्पर निर्भरता की कमजोरियों को उजागर किया। 1989–90 के व्यापार और पारगमन विवाद के दौरान, नई दिल्ली द्वारा अलग–अलग संधियों को नवीनीकृत न करने के निर्णय के कारण 16 महीने की आभासी नाकेबंदी हुई, मिट्टी के तेल, नमक और चिकित्सा आपूर्ति की कमी ने सबसे पहले तराई को पंगु बना दिया, जिससे भारत विरोधी भावना भड़की और संवैधानिक सुधार की मांग तेज हो गई।

1990 के लोकतांत्रिक संविधान के बाद भेदभाव और कम प्रतिनिधित्व को लेकर मधेशियों की शिकायतें स्पष्ट हुईं, लेकिन जन आंदोलन ॥ (2006) और मधेश आंदोलन ।और॥ (2007–2008) में ही जोरदार ढंग से उभरीं, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए और काठमांडू को संघीय पुनर्गठन और आनुपातिक समावेशन की गारंटी के लिए अंतरिम संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा[8]। फिर भी, बाद के 2015 के संविधान ने केवल आठ तराई–बहुल जिलों को प्रांत 2 में विभाजित किया, जिससे विरोध प्रदर्शन फिर से भड़क उठे और बीरगंज–रक्सौल गलियारे की 135 दिनों की नाकेबंदी हुई, जिससे ईंधन ट्रकों की दैनिक आवाजाही लगभग 300 से घटकर दस से भी कम हो गई। मैदानी इलाकों के अस्पतालों में रक्त की थैलियां और आवश्यक दवाएं खत्म हो गईं, जबकि नेपाल ने अपनी दक्षिणी निर्भरता समाप्त करने के लिए जल्दबाजी में चीन के साथ पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए।

मधेशी क्षेत्र का सामाजिक–जनसांख्यिकीय और आर्थिक स्वरूप

मधेश प्रांतकृनेपाल का पूर्वी–मध्य तराई क्षेत्र के लिए संवैधानिक पदनामकृकेवल 9,661 वर्ग किमी क्षेत्रफल में 61.1 लाख निवासियों का निवास करता है, जिसका जनसंख्या घनत्व 633 व्यक्ति/वर्ग किमी है, जो देश में सबसे अधिक है और नेपाल की कुल जनसंख्या का 20.97 प्रतिशत है। भाषाई और सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र मैथिली, भोजपुरी और अवधी भाषी मधेशियों, पर्याप्त था, समुदायों और मुस्लिम आबादी (बारा जिले में 14.7 प्रतिशत) का मिश्रण है, जो राष्ट्रीय औसत 5 प्रतिशत से अधिक है[9]। फिर भी विकासात्मक संकेतक पिछड़े हुए हैं 2021 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 63.5% दर्ज की गई है—जो नेपाल के सात प्रांतों में सबसे कम है—और पुरुष–महिला अंतर 17.8 प्रतिशत अंकों का है, जो दशकों से चली आ रही सकारात्मक–समावेश नीतियों के बावजूद सामाजिक बहिष्कार की जड़ें जमाए हुए है।

आर्थिक रूप से, समतल जलोढ़ मैदान नेपाल की प्राथमिक अनाज की टोकरी है। 2019 के एक क्षेत्रीय अध्ययन ने अनुमान लगाया कि तराई की जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय दर से मामूली अधिक है, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर पर 610 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 629 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग और बीरगंज–पथलैया गलियारे के साथ औद्योगिक गतिविधि समूह, जहां चीनी, कपड़ा और कृषि प्रसंस्करण मिलों में भारतीय इक्विटी प्रमुख है। महत्वपूर्ण रूप से, नेपाल के पांच सबसे अधिक मात्रा वाले सीमा शुल्क गेटवे में से चार– बीरगंज, विराटनगर, भैरहवा और नेपालगंज–मधेश में स्थित हैं[10]। अकेले बीरगंज ने वित्त वर्ष 2024/25 के पहले ग्यारह महीनों में एनपीआर 565.4 बिलियन (लगभग 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के आयात और एनपीआर 91.5 बिलियन के निर्यात को संभाला इसी पोस्ट ने इस अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों से 174 अरब नेपाली रुपये का आयात किया और 140 अरब नेपाली रुपये से अधिक का सीमा शुल्क राजस्व जुटाया, जिससे यह नेपाल के खजाने में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया।

उच्च बाहरी श्रम प्रवासन सीमावर्ती अर्थव्यवस्था को और भी उलझा देता है। घरेलू सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आधे से ज़्यादा मधेशी प्रवासी मजदूर पड़ोसी भारतीय राज्यों को अपना ठिकाना चुनते हैं, जिससे धन प्रेषण की जीवनरेखा बनी रहती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद के लगभग एक–चौथाई के बराबर है[11]। ये जनसांख्यिकीय मजबूती, व्यापार धमनियाँ और आजीविका सर्किट मिलकर मधेशियों को न केवल नेपाल का कृषि प्रधान केंद्र बनाते हैं, बल्कि देश की वित्तीय और ऊर्जा सुरक्षा का एक अनिवार्य आधार भी बनाते हैं।

तराई सीमावर्ती क्षेत्रों का भू–रणनीतिक महत्व

मधेसी मैदान, हिमालय–प्रधान देश में समतल स्थलाकृति का एक दुर्लभ, निर्बाध विस्तार है। यह नेपाल के प्रमुख स्थलीय गलियारे 1028 किलोमीटर लंबे महेंद्र (पूर्व–पश्चिम) राजमार्ग का घर है, जो तराई के 24 जिलों में से 23 को जोड़ता है और भारत की ओर जाने वाली प्रत्येक प्रमुख उत्तर–दक्षिण फीडर सड़क को जोड़ता है[12]। सीमा के निकट डाक राजमार्ग के समानांतर यह अक्षीय मार्ग, व्यापार को चार सीमा शुल्क अवरोध बिंदुओं—बीरगंज–रक्सौल, विराटनगर–जोगबनी, भैरहवा–सुनौली और नेपालगंज–रुपैदिहा तक पहुँचाता है, जो मिलकर नेपाल के दो–तिहाई से अधिक व्यापारिक व्यापार का संचालन करते हैं। अकेले बीरगंज ने वित्त वर्ष 2024/25 के पहले ग्यारह महीनों में 565.4 अरब नेपाली रुपये मूल्य के आयात और 91.5 अरब नेपाली रुपये मूल्य के निर्यात का निपटान किया[13]।

इन प्रवेश द्वारों की रुकावटों को दूर करने के लिए, भारत और नेपाल ने इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग, क्वारंटाइन लैब और सिंगल–विंडो कस्टम्स से सुसज्जित एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) में अपग्रेड किया है। अप्रैल 2018 में दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किए गए बीरगंज आईसीपी के बाद जनवरी 2020 में जोगबनी–विराटनगर का उद्घाटन किया गया। भैरहवा में तीसरी सुविधा निर्माणाधीन है। सड़क रसद के पूरक के रूप में, सीमा पार जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा ब्रॉड–गेज रेलवे अब तीन दैनिक सेवाएं चलाती है, और बर्दीबास तक अंतिम 17 किलोमीटर के हिस्से के लिए सर्वेक्षण कार्य – जो सीधे पूर्व–पश्चिम रेल गलियारे से जुड़ता है – दिसंबर 2023 में भारतीय वित्तपोषण से शुरू हुआ। ये बहुविध धमनियां तराई को न केवल नेपाल की बंदरगाहों तक पहुंच के लिए, बल्कि सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से अपने पूर्वोत्तर को जोड़ने की भारत की अपनी उप–क्षेत्रीय योजनाओं के लिए भी अपरिहार्य बनाती हैं[14]।

ऊर्जा सुरक्षा तराई के सामरिक महत्व को और बढ़ाती है। 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी–अमलेखगंज पाइपलाइन दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम लाइन पहले से ही नेपाल की डीजल की जरूरतों को पूरा करती है और फरवरी 2025 के उन्नयन के बाद, अब पेट्रोल और केरोसिन भी पहुँचाएगी, जिसकी भंडारण क्षमता 16,630 किलोलीटर और डिजाइन क्षमता 2 एमएमटीपीए तक बढ़ाई गई है। बिजली के क्षेत्र में, मधेश प्रांत से होकर गुजरने वाली धालकेबार–मुजफ्फरपुर 400 केवी लाइन एकमात्र उच्च क्षमता वाली ग्रिड इंटरकनेक्शन बनी हुई है। फरवरी 2025 में होने वाले एक समझौते से इसकी स्थानांतरण सीमा 800 मेगावाट से बढ़कर लगभग 1,100 मेगावाट हो जाएगी,

जबकि दो अतिरिक्त 400 केवी लिंक इनारुवा–न्यू पूर्णिया और दोधारा–बरेली एक संयुक्त उद्यम कंपनी के तहत तैयार किए जा रहे हैं। ये संपत्तियाँ काठमांडू के ऊर्जा परिवर्तन और अगले दशक में 10 गीगावाट नेपाली जलविद्युत खरीदने की दिल्ली की प्रतिज्ञा को मधेश के भूगोल में सुरक्षित करती हैं[15]।

सुरक्षा गणना इन आर्थिक दांवों को भी शामिल करती है। भारत की सशस्त्र सीमा बल ने 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा पर 282 सीमा चौकियाँ स्थापित की हैं, और खुली सीमा के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अपराध और चरमपंथी घुसपैठ के बारे में बार–बार अलर्ट मिलने के बाद ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से स्तरित गश्त कर रही है। नेपाल की ओर, सशस्त्र पुलिस बल ने चौबीसों घंटे गश्त बढ़ा दी है और तस्करी तथा अवैध प्रवास को रोकने के लिए प्रांत 1 और मधेश में नए सीमा शिविर स्थापित करने की योजना बना रही है[16]।

मधेसी क्षेत्र में भारत के 6 प्रमुख हित

नई दिल्ली से देखा जाए तो, नेपाल के तराई क्षेत्र से सटी 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा एक साथ सुरक्षा बफर, ऊर्जा की नाभि और भारत के स्थल–आबद्ध पूर्वोत्तर के लिए एक रसद प्रवेश द्वार है। सुरक्षा एजेंसियों को चिंता है कि जिस सरंध्रता के कारण हर साल 5–6 मिलियन लोग सीमा पार आवाजाही करते हैं, उसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों और जाली मुद्रा की तस्करी के लिए भी किया जाता है। जुलाई 2025 की शुरुआत में सशस्त्र सीमा बल ने पिलर 277/01 के पास 344 किलोग्राम गांजा जब्त किया था, जबकि एक महीने पहले जयनगर सेक्टर में अज्ञात "ड्रोन जैसी चमकदार वस्तुओं" की एक श्रृंखला के कारण हाई–अलर्ट जारी कर दिया गया था। इसलिए दोनों राजधानियों के सीमा शुल्क प्रमुखों ने अप्रैल 2025 में मधेस क्षेत्र में संचालित सोने, नशीले पदार्थों और जाली मुद्रा के रैकेट के खिलाफ संयुक्त गश्त, रीयल–टाइम डेटा साझाकरण और समन्वित अभियोजन को तेज करने पर सहमति व्यक्त की[17]।

फिर भी, भारत के दांव कानून–व्यवस्था से कहीं ज्यादा गहरे हैं। तराई क्षेत्र नेपाल के दक्षिण की ओर जाने वाले बिजली और पेट्रोलियम के लगभग पूरे प्रवाह को वहन करता है, जिन वस्तुओं को अब दिल्ली रणनीतिक मानता है। दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार ईंधन लाइन, 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी–अमलेखगंज पाइपलाइन ने दिसंबर 2024 में पेट्रोल और केरोसिन के लिए परीक्षण पूरा कर लिया है और जनवरी 2025 के बाद यह 6,000 किलोलीटर प्रतिदिन तक संचालित होगी, जिससे दोनों तरफ टैंकर यातायात और चोरी से होने वाले नुकसान में कमी आएगी। बिजली के क्षेत्र में, भारत का जनवरी 2024 का दीर्घकालिक बिजली–व्यापार समझौता अगले दशक में 10 गीगावाट नेपाली जलविद्युत खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। यह समझौता तभी सार्थक होगा जब मधेश प्रांत से होकर गुजरने वाले धालकेबार–मुजफ्फरपुर 400 केवी कॉरिडोर को 800 मेगावाट से बढ़ाकर लगभग 1,100 मेगावाट कर दिया जाए, जो फरवरी 2025 में स्वीकृत एक क्षमता–वृद्धि योजना है[18]।

आर्थिक रूप से, चार तराई सीमा शुल्क चौकियाँ नेपाल के दो–तिहाई से अधिक आयात और भारत को उसके लगभग 95% निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं। अकेले बीरगंज एकीकृत चेक पोस्ट ने वित्त वर्ष 2024/25 के पहले ग्यारह महीनों में लगभग 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के माल की निकासी की[19]। कोई भी आपूर्ति झटका जैसे कि 2015 की 135 दिन की नाकेबंदी – बिहार और उत्तर प्रदेश में तुरंत प्रभाव डालता है, जहां कृषि प्रसंस्करण, उर्वरक और लघु–भाग उद्योगों का घना जाल निर्बाध नेपाली कच्चे माल या श्रम प्रवाह पर निर्भर करता है।

नेपाल की घरेलू राजनीति और संघवाद पर बहस

काठमांडू के लिए, मधेश एक साथ ही अपने अभी भी नवजात संघीय गणराज्य की कसौटी और दबाव–वाल्व है। 2015 के संविधान ने पहचान–आधारित संघवाद, आनुपातिक समावेशन और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व का वादा किया था, फिर भी केवल एक स्पष्ट रूप से मैदानी–बहुमत वाली इकाई – मधेश प्रांत – प्रदान की और नागरिकता हस्तांतरण और प्रांतीय वित्तीय स्वायत्तता जैसे विवादास्पद

मुद्दों को अनसुलझा छोड़ दिया। नौ साल बाद भी, इन अंतरालों का राजनीतिक महत्व स्पष्ट है। संविधान दिवस 2024 पर, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संविधान को बहिष्कारवादी बताते हुए उसकी निंदा करने के लिए काली पट्टियाँ पहनीं, जबकि जनमत के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार ने जश्न में तेल के दीये जलाए – एक ऐसा स्प्लिट–स्क्रीन जिसने कभी एकजुट मधेशी आंदोलन के विखंडन को कैद कर लिया[20]।

फिर भी, इस विखंडन ने राष्ट्रीय गठबंधनों में इस क्षेत्र के प्रभाव को कम नहीं किया है। जून 2025 में उपेंद्र यादव की जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) ने प्रधानमंत्री के.पी. ओली के बहुदलीय गठबंधन के साथ गठबंधन टूटने से सरकार राष्ट्रीय सभा में अल्पमत में आ गई और किसी भी संभावित संवैधानिक संशोधन के लिए उसके दो–तिहाई अंकगणित पर खतरा मंडराने लगा। इससे पहले, अप्रैल 2025 में, सात मैदानी–आधारित ताकतें जिनमें जेएसपी, एलएसपी और उभरती जनमत पार्टी शामिल थीं। संघीय लोकतांत्रिक मोर्चे के रूप में एक साथ मिलकर 26–सूत्रीय मंच बनाया था, जिसमें सीमा–आधारित राजस्व–बंटवारे से लेकर लैंगिक–समान नागरिकता और भाषाई अधिकारों तक शामिल थे। वैचारिक रूप से भले ही यह गुट ढीला–ढाला हो, लेकिन चार्टर में अगले दौर के बदलावों पर सामूहिक रूप से बातचीत करने के नए सिरे से प्रयास का संकेत देता है[21]।

संस्थागत रूप से, संघीय व्यवहार एक मिश्रित स्थिति को दर्शाता है। बर्टेल्समैन परिवर्तन सूचकांक 2024 नेपाल को स्वतंत्र प्रांतीय चुनावों के दूसरे चक्र के आयोजन और राज्य क्षमता में सुधार का श्रेय देता है, लेकिन लगातार केंद्रीय अतिक्रमण, अपर्याप्त वित्तपोषित प्रांतीय नौकरशाही और विलंबित वित्तीय हस्तांतरण की ओर इशारा करता है। ये सभी चिंताएँ मधेश में और बढ़ जाती हैं, जहाँ स्थानीय राजस्व आवर्ती खर्च का मुश्किल से एक चौथाई हिस्सा ही पूरा कर पाता है[22]।

बाहरी शक्ति प्रतिस्पर्धा: चीन का विस्तार–फिर भी असमान पदचिह्न

मधेसी मैदान में अब दिल्ली का सामना केवल काठमांडू से नहीं है। 2017 में नेपाल के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल होने के बाद से, बीजिंग ने तराई को अपने ट्रांस–हिमालयन मल्टी–डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (THMDCN) के दक्षिणी केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया है। प्रमुख परियोजनाओं में लंबे समय से प्रस्तावित जिलोंग–काठमांडू रेलवे और एक त्रिपक्षीय आर्थिक गलियारा शामिल है जो चीन के शिगात्से लॉजिस्टिक्स पार्क को बीरगंज और आगे भारत के पूर्वी माल ढुलाई ग्रिड से जोड़ेगा[23]।

काठमांडू पोस्ट द्वारा जून 2025 में की गई एक जांच में पाया गया कि दस प्राथमिकता वाली बीआरआई परियोजनाओं में से कोई भी जिनमें केरुंग–काठमांडू रेलवे, तमोर हाइड्रोपावर कैस्केड और तोखा–छाहारे सुरंग शामिल हैं। ऋण–स्थायित्व संबंधी चिंताओं और कोविड–19 में देरी का हवाला देते हुए, पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन से आगे नहीं बढ़ पाई है। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीआरआई की एकमात्र पूरी हो चुकी परियोजना, जनवरी 2023 में खुलेगी, लेकिन अनुमानित क्षमता के बमुश्किल 20 प्रतिशत पर ही संचालित हो रही है, अगस्त 2024 में नेपाल ने औपचारिक रूप से चीन से अपने 25.9 अरब रुपये के एक्जिम–बैंक ऋण को अनुदान में बदलने का अनुरोध किया[24]।

फिर भी, बीजिंग की सॉफ्ट–पावर का प्रभाव बढ़ रहा है। 1 दिसंबर 2024 से चीन ने 8,000 नेपाली उत्पादों को शून्य–शुल्क पहुंच प्रदान की शर्मा ओली की दिसंबर 2024 की बीजिंग यात्रा ने "भारत से दूर हटने" का संकेत दिया, क्योंकि उन्होंने चीन निर्मित हवाई अड्डों और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निवेश आश्वासन और प्रतीकात्मक उड़ान अधिकार मांगे[25]।

दिल्ली के लिए, ये घटनाक्रम एक पारंपरिक छोटे राज्य की सुरक्षा दुविधा को स्पष्ट करते हैं। अपने रणनीतिक विकल्पों को व्यापक बनाने का नेपाल का प्रत्येक प्रयास प्रति–उपायों त्वरित आईसीपी निर्माण, विस्तारित पेट्रोलियम और बिजली पाइपलाइनों को बाध्य करता है, जो मधेश–केंद्रित परस्पर निर्भरता को और गहरा करते हैं, जबकि चीन विकल्पों का वादा करता है। इस प्रकार सीमावर्ती क्षेत्र दोहरी कनेक्टिविटी चालों का एक रंगमंच बन जाता है[26]।

नीतिगत विकल्प और रणनीतिक सुझाव

1. तराई आर्थिक गलियारे (TEC) को संस्थागत रूप दें। मौजूदा ICP–रेल–पाइपलाइन क्लस्टर को बांग्लादेश–भूटान–भारत–नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते की तर्ज पर एक कानूनी रूप से समर्थित उप–क्षेत्रीय आर्थिक क्षेत्र में उन्नत करें ताकि बुनियादी ढाँचा, SPS मानदंड और डिजिटल भुगतान ढाँचा टुकड़ों में न होकर सह–डिजाइन किया जा सके।
2. सममित संघीय समर्थन को मजबूत करें। भारत की अनुदान परियोजनाओं को नेपाल की अंतर–प्रांतीय परिषद के माध्यम से प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि काठमांडू को नजरअंदाज करने की धारणा से बचा जा सकेय इसके विपरीत, काठमांडू को पारदर्शी राजस्व–साझाकरण सूत्र प्रकाशित करने चाहिए जिससे मधेश को सीमा शुल्क आय का एक अनुमानित हिस्सा मिल सके।
3. त्रि–राष्ट्रीय आपदा–प्रतिरोधक समझौता। कोशी की वार्षिक बाढ़ सीमा स्तंभों को नष्ट कर देती है और अतिक्रमण के दावों को बढ़ावा देती है। भारत–नेपाल–चीन के बीच जल–मौसम संबंधी आंकड़ों का संयुक्त आदान–प्रदान और पूर्व–चेतावनी प्रोटोकॉलकृचीन के अपस्ट्रीम गेजों का लाभ उठाते हुएकृ त्रासदियों की रोकथाम को एक विश्वास–निर्माण उपाय में बदल देगा।
4. सुरक्षा क्षेत्र में विश्वास निर्माण। 2014 के सीमा–पार अपराध नियंत्रण समझौते का विस्तार करके पूर्वनिर्धारित "रेड–फ्लैग" क्षेत्रों में एसएसबी–एपीएफ की मिश्रित गश्त की अनुमति दी जाए, जिसे प्रांतीय पुलिस प्रमुखों और भारत की बीएसएफ पूर्वी कमान के बीच एक हॉटलाइन द्वारा पूरक बनाया जाए।

निष्कर्ष

मधेश न तो केवल कृषि प्रधान क्षेत्र है और न ही एक निष्क्रिय बफर, यह वह धुरी है जिस पर अब दक्षिण एशिया के सबसे नाजुक विषम संबंध टिके हुए हैं। दो शताब्दियों का इतिहास दर्शाता है कि मधेशियों के समावेश की उपेक्षा द्विपक्षीय संकट को मजबूती से जन्म देती है, जबकि अति उत्साही बाहरी प्रणय निवेदन प्रति–संतुलन को जन्म देता है। आज, भारत की ऊर्जा पाइपलाइनें और चीन के महत्वाकांक्षी रेलवे स्टेशन उसी बाढ़–प्रवण मैदान पर मिलते हैं, जिसके निवासी अभी भी नेपाल में सबसे कम साक्षरता और वित्तीय–हस्तांतरण अनुपात से जूझ रहे हैं। इन विरोधाभासों को सुलझाने के लिए सीमा–भूमि शासन की आवश्यकता है जो स्थानीय रूप से सशक्त, संघीय रूप से वैध और क्षेत्रीय रूप से पारदर्शी हो। इस शोधपत्र में प्रतिद्वंद्विता के कारणों, पहचान की राजनीति, रसद संबंधी अड़चनें, महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का पता लगाया गया है और एक सहकारी तराई आर्थिक गलियारे की ओर मार्ग प्रशस्त किया गया है। काठमांडू, दिल्ली और बीजिंग इस दृष्टिकोण पर एकमत हो पाते हैं या नहीं, यह तय करेगा कि मधेश चिरस्थायी विवाद के बिंदु से विकसित होकर एक अधिक एकीकृत पूर्वी उपमहाद्वीप के लिए एक संयोजक ऊतक बन पाता है या नहीं।

संदर्भ सूचीः

[1] एंडरसन, जे. (2020), बॉर्डर्सः अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पृष्ठ 16–30
[2] अधिकारी, आई. (2019), द हिस्ट्री ऑफ नेपालीज बॉर्डर मेकिंग, रूटलेज, पृष्ठ 51–94
[3] बराल, एल. आर. (2012), नेपाल—नेशन–स्टेट इन द वाइल्डर्नेसः मैनेजिंग स्टेट, डेमोक्रेसी एंड जियोपॉलिटिक्स, सेज, पृष्ठ 10–25
[4] भट्टाराई, बी., एवं वाग्ले, एस. (2022), इंडियाज फ्यूल–लाइन डिप्लोमेसी इन नेपालः मोतीहारी अमलेखगंज इन पर्सपेक्टिव, एनर्जी पॉलिसी, 168, पृष्ठ 111–124
[5] ब्रुनेट–जेयी, ई. (2021), बॉर्डरलैंड थ्योरीः एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क, जर्नल ऑफ बॉर्डरलैंड्स स्टडीज, 36 (4), पृष्ठ 527–547
[6] सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, (2022), नेशनल पॉप्युलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2021ः मधेश प्रांत (वॉल्यूम II), पृष्ठ 17–35

[7] चौल्या, एस. (2020), ट्रम्प्डः इमरजिंग पॉवर्स इन अ पोस्ट–अमेरिकन वर्ल्ड, ब्लूम्सबरी इंडिया, पृष्ठ 105–114

[8] दहाल, डी. आर. (2019), मधेस उपराइजिंग्स एंड फेडरल रिस्ट्रक्चरिंग इन नेपाल, स्टडीज इन नेपाली हिस्ट्री एंड सोसाइटी, 24 (1), पृष्ठ 1–28

[9] भारतीय दूतावास, काठमांडू. (2025), इंडिया नेपाल डेवलपमेंट पार्टनरशिपः फैक्ट शीट, पृष्ठ 1–18

[10] गुरुङ, एच. (2017), फेसेज ऑफ नेपाल (द्वितीय संस्करण), पृष्ठ 10–28

[11] नेपाल सरकार एवं भारत सरकार, (2023), 14वीं नेपाल इंडिया जॉइंट कमीशन की कार्यवृत्त, विदेश मंत्रालय, नेपाल , पृष्ठ 1–25

[12] इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, (2020), नेपाल अंडर स्ट्रेसः पॉलिटिकल क्राइसिस एंड द मधेशी क्वेश्चन (एशिया रिपोर्ट संख्या 326), पृष्ठ 12–18

[13] झा, पी. (2014), बैटल्स ऑफ द न्यू रिपब्लिकः अ कंटेम्पररी हिस्ट्री ऑफ नेपाल, पृष्ठ 40–115

[14] कान्तिपुर डेली, (14 फरवरी 2025), एपीएफ ने सरलाही सीमा पर संयुक्त गश्त तेज की, कान्तिपुर, पृष्ठ 3

[15] लावोटी, एम. (2019), री–इमेजिनिंग द नेशनः फेडरलिज्म, इन्क्लूजन एंड आइडेंटिटी इन नेपाल, साउथ एशियन स्टडीज, 42 (4), पृष्ठ 625–641

[16] ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाई मंत्रालय, (2025), क्रॉस–बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड स्टेटस रिपोर्ट, नेपाल सरकार, पृष्ठ 15–30

[17] गृह मंत्रालय, भारत, (2024), वार्षिक रिपोर्ट 2023–24, भारत सरकार पृष्ठ 37–114

[18] मिश्रा, बी. (2023), साउदर्न प्लेन्सः हिस्ट्री, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल्स मधेस, पृष्ठ 1–40

[19] मर्टन, जी., लॉर्ड, ए., एवं बीजली, आर. (2021), अ हिमालयन बॉर्डरलैंड एंड इट्स मार्जिन्सः एवरीडे जियोपॉलिटिक्स इन द तराई, पॉलिटिकल जियोग्राफी, 89, पृष्ठ 102423–102439

[20] राष्ट्रीय योजना आयोग, (2023), पंद्रहवीं योजना (2019/20–2023/24) मध्यावधि समीक्षा, नेपाल सरकार पृष्ठ 12–55

[21] पांडेय, आर. (2022), रिविजिटिंग द 1950 ट्रीटीः असीमेट्री एंड एजेंसी इन इंडिया–नेपाल रिलेशन्स, इंटरनेशनल स्टडीज, 59 (2), पृष्ठ 168–186

[22] पंत, एच. वी., एवं लामा, एन. के. (2024), इंडियाज 'नेबरहुड फर्स्ट' एंड इट्स लिमिट्सः द नेपाल ब्लॉकेड रिविजिटेड, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, 48 (1), पृष्ठ 73–89

[23] पोखरेल, एस. (3 मार्च 2025), बीआरआई परियोजनाएँ वित्तीय मॉडल पर भिन्नता के कारण अधर में, द काठमांडू पोस्ट, पृष्ठ 1–2

[24] शुक्ला, ए. (2024), सशस्त्र सीमा बल एवं भारत की बॉर्डर–मैनेजमेंट चुनौतियाँ, आईडीएसए इश्यू ब्रीफ, पृष्ठ 1–15

[25] सिंह, सी. एस. (सम्पा.), (2023), इंडिया–नेपाल रिलेशन्सः पॉलिटिकल, इकॉनमिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशन्स, पेंटागन प्रेस, पृष्ठ 15–42

[26] विश्व बैंक (2024), नेपाल डेवलपमेंट अपडेट, अक्टूबर 2024ः इन्वेस्टिंग इन कनेक्टिविटी, विश्व बैंक समूह, पृष्ठ 14–18